

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-210/2017/बांसवाड़ा

शम्भूलाल हिरण पुत्र गणेशीलाल हिरण, आयु 56 वर्ष, जाति जैन, निवासी नाथेलाव
कॉलोनी, बांसवाड़ा
बनामप्रार्थी

1. सरकार जरिये कलकटर (मुद्रांक), उदयपुर।
2. शान्तिलाल पुत्र चम्पालाल, आयु 72 वर्ष, जाति जैन, निवासी पालोदा, हाल
बांसवाड़ा, तहसील व जिला बांसवाड़ाअप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नथूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पी. गण्डेविया एवं शफिक मौहम्मद
अभिभाषकप्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप-राजकीय अभिभाषकअप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 14.03.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलकटर (मुद्रांक) उदयपुर कैम्प बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कलकटर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 12.10.2011 प्रकरण संख्या 32/2008 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक कोलायत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक विक्रय दस्तावेज वास्ते पंजीयन हेतु उप-पंजीयक बांसवाड़ा के समक्ष दिनांक 27.04.2014 को प्रस्तुत किया गया। इस पर दस्तावेज का पंजीयन किया जाकर प्रार्थी को लौटा दिया गया। इसके पश्चात् जांच दल द्वारा उपपंजीयक कार्यालय की ऑडिट किये जाने पर उक्त दस्तावेज को कमी मालियत माना जिसके आधार पर उपपंजीयक बांसवाड़ा अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया। सूचना-पत्र प्राप्ति पर प्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र दिनांक 18.12.09 को प्रस्तुत किया तथा मुद्रांक कर की मांग को उचित नहीं बताया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा रेफरेन्स को स्वीकार करते हुये दस्तावेज की मालियत 6411322/- रु. निर्धारित कर मुद्रांक कर 416740/- रु. एवं पंजीयन शुल्क 25000/- रु. देय मानते हुये प्रार्थी द्वारा पूर्व में अदा किये गये मुद्रांक कर

२८

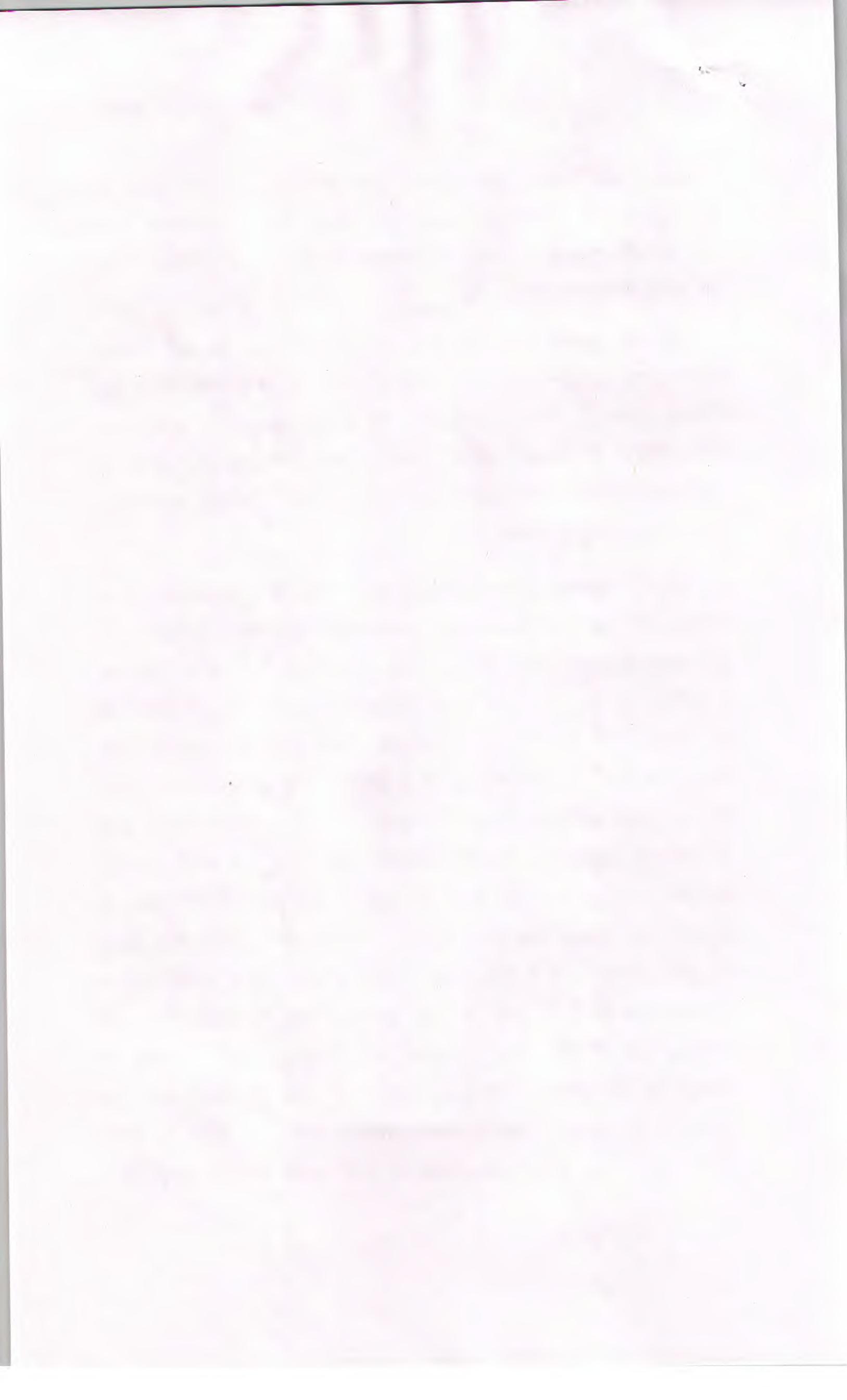
लगातार.....2



151540/- रु. पंजीयन शुल्क 23320/- की कमी करते हुये कमी मुद्रांक कर 265200/-रु कमी पंजीयन शुल्क 1680/- एवं शास्ति 3120/- रु. कायम की गई तथा कुल राशि 2,70,000/- वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी ग्राहयता के स्तर पर सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। प्रकरण में विचाराधीन बिन्दु अन्य निगरानी संख्या 358/2012/बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 09.01.17 व 1036/2016 निर्णय दिनांक 31.01.2017 के समान होने के कारण उभयपक्ष की सहमति पर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण किया जाना उचित मानते हुए बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि कलक्टर मुद्रांक उदयपुर का निर्णय एक नॉन स्पीकिंग एवं साईक्लोस्टाईल ऑर्डर है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ना तो हवाला देकर सम्पत्ति जो जैल रोड पर स्थित थी, के संबंध में पूर्व बेचाननामे आदि अवलोकन किये बिना ए.जी. द्वारा जो आपत्ति की गई थी जो स्वीकार कर प्रार्थी के साथ घोर अन्याय किया है। कलक्टर मुद्रांक उदयपुर ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना अकारण ही एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से प्रार्थी के साथ घोर अन्याय किया गया है। कलक्टर मुद्रांक उदयपुर ने सम्पत्ति जो जैल रोड बस स्टैण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाड़ा होते हुए की डी.एल.सी. के अनुसार, मौका निरीक्षण किये बिना ए.जी. की सिफारिश के आधार पर कमी मुद्रांक का आदेश पारित करने में भारी गलती की है। कलक्टर मुद्रांक ने इस बात को नरजअंदाज किया है कि प्रार्थी ने जैल रोड बस स्टैण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाड़ा होते हुए की दर से मुद्रांक की राशि अदा कर बेचाननामा निष्पादित करवाया था जो विधिवत् होने से उपपंजीयक बांसवाड़ा ने उचित मानते हुए बेचाननामा पंजीकृत कर प्रार्थी ने असल दस्तावेज लौटा दिया था। उस कारण कलक्टर मुद्रांक द्वारा कमी मुद्रांक बताकर जो आदेश पारित किया है त्रुटिपूर्ण है



विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलाकेन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. निगरानी में निगरानीकर्ता का मुख्य आधार यह है कि कलकटर मुद्रांक उदयपुर का निर्णय एक नॉन स्पीकिंग एवं साईक्लोस्टाईल ऑर्डर है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ना तो हवाला देकर सम्पत्ति जो जैल रोड पर स्थित थी, के संबंध में पूर्व बेचाननामे आदि अवलोकन किये बिना ए.जी. द्वारा जो आपत्ति की गई थी जो स्वीकार कर प्रार्थी के साथ अन्याय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई मौका निरीक्षण व जांच किये रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

रेफरेन्स ऑफिट आक्षेप के इस बिन्दु पर आधारित था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति जैल रोड बस स्टेंड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाड़ा होते हुये मानकर मूल्यांकन किया है जबकि सम्पत्ति गांधी मूर्ति चौराहे से कर्स्टम चौराहे तक पुराना जैल रोड पर स्थित हैं तथा इसी अनुरूप डी.एल.सी. के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के तथ्यों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार जांच की है व न ही अपने निर्णय में तथ्यों के संबंध में कोई विवेचना या विश्लेषण किया है। अधीनस्थ न्यायालय



के निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स

(Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :—

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been



properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य है।

9. प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि सम्पत्ति की लोकेशन कहा है अर्थात् सम्पत्ति जेल रोड बस स्टेण्ड से चन्द्रपोल गेट तक मोचीवाड़ा होते हुए पर स्थित है या गांधी मूर्ति चौराहे से कस्टम चौराहे तक पुराना जेल रोड पर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई जांच नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए जांच कर व 65(4)(iv) के अन्तर्गत उभयपक्ष को नोटिस देकर स्थल निरीक्षण कर संपत्ति का लोकेशन का निर्धारण करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार एवं विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 12.10.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए एवं राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.04.2017 को पेश हों।

11. निर्णय सुनाया गया।

१५२७
(नथूराम)
सदस्य

